इकाई 9 विशेष क्षेत्र का विकास कार्यक्रम

इकाई की रूपरेखा

9.0 लक्ष्य और उद्देश्य

9.1 परिचय

9.2 विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रमों से संबंधित अवधारणाएं और परिभाषाएँ

  9.2.1 क्षेत्र

  9.2.2 नियोजन

  9.2.3 क्षेत्रीय योजना

  9.2.4 कार्यक्रम

  9.2.5 विशेष क्षेत्र

9.3 विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रमः नीति और कार्यान्वयन

  9.3.1 पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एचएडीपी)

  9.3.2 जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (टीएडीपी)

  9.3.3 पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम (डब्ल्यूजीडीपी)

  9.3.4 सूखा प्रवण क्षेत्र विकास कार्यक्रम (डीपीएडीपी)

  9.3.5 मरुस्थल विकास कार्यक्रम (डीडीपी)

  9.3.6 सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी)

9.4 आइए संक्षेप में बताते हैं

9.5 मुख्य शब्द

9.6 सुझाए गए अध्ययन और संदर्भ

9.0 लक्ष्य और उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद, आप समझ पाएंगेः

- क्षेत्रीय विकास, योजना, विशेष क्षेत्रों और विशेष क्षेत्रों की योजनाओं की अवधारणाओं के बीच अंतर;
- विशेष क्षेत्र योजनाओं के प्रकार;
- विशेष क्षेत्र विकास योजनाओं की आवश्यकता; और
- नीति और विभिन्न विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रमों का कार्यान्वयन।

9.1 परिचय

एक विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रम संतुलित क्षेत्रीय विकास के लिए भारत की नियोजन नीति का हिस्सा है; जो उन विशिष्ट क्षेत्रों के विकास पर केंद्रित है; जो देश के अन्य हिस्सों के साथ तालमेल रखने में विफल रहे। यह एक महत्वपूर्ण विकास कार्यक्रम है जिसे असंतुलन को कम करने और उस क्षेत्र के आर्थिक विकास को गति देने के लिए पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया है। भारत में क्षेत्रीय विकास को संतुलित करना, इसके आकार और विविधता के कारण एक चुनौतीपूर्ण कार्य है।

ignou THE PEOPLE'S UNIVERSITY

देश के विभिन्न क्षेत्रों के बीच असमानता समय के साथ बढ़ी है, इसने संसाधनों के असमान वितरण के संदर्भ में भिन्नता पेश की है। भारत में आर्थिक और सामाजिक विकास का अध्ययन विभिन्न स्तरों पर किया जाता रहा है। सबसे आम इकाई राज्य स्तर है। हालांकि, एक समृद्ध राज्य में कई पॉकेट/क्षेत्र हैं, जो पिछड़े और अविकसित हैं। यह विशेष रूप से विविध भौगोलिक, आर्थिक और सामाजिक विशेषताओं के कारण है। परिदृश्य के कारण कुछ क्षेत्र पिछड़े हुए हैं, उदाहरण के लिए, पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्र, विशिष्ट सांस्कृतिक समूह यानी आदिवासी क्षेत्र, समस्याग्रस्त और शत्रुतापूर्ण वातावरण यानी अनुत्पादक मिट्टी, रेगिस्तानी क्षेत्र और सूखा प्रवण क्षेत्र, और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र यानी पश्चिमी घाट आदि। इन क्षेत्रों को अपने भौगोलिक और सामाजिक-आर्थिक वातावरण के अनुसार न केवल विकास के लिए बल्कि अन्य क्षेत्रों की तरह फलने-फूलने के लिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

प्रो. आर.पी. मिश्रा, "क्षेत्रीय विकास क्षेत्रीय नियोजन के माध्यम से किया जाता है जो उप-राष्ट्रीय क्षेत्रों की क्षमता का मूल्यांकन करने और उन्हें समग्र रूप से राष्ट्र के सर्वोत्तम लाभों के लिए विकसित करने की एक तकनीक है"।

जैसा कि हम जानते हैं कि क्षेत्रीय विकास का उद्देश्य सामाजिक-आर्थिक विकास के माध्यम से क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करना और देश के अन्य क्षेत्रों के बराबर क्षेत्र के पिछड़ेपन को समाप्त करना है। इस संबंध में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर रिपोर्ट तैयार करने और इन क्षेत्रों में पिछड़ेपन के स्तर का आकलन करने के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया गया है। अंत में, चौथी योजना (1969-74) में पहली बार भौतिक, आर्थिक और सामाजिक संरचनाओं सहित स्थानीय मुद्दों और चुनौतियों पर विचार करते हुए इन विशिष्ट क्षेत्रों में विशेष क्षेत्र विकास योजनाएं कार्यान्वित की गईं। विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम जैसे पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम, सूखा प्रवण क्षेत्र विकास कार्यक्रम, मरुस्थल विकास कार्यक्रम, पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम और जनजातीय उप-योजनाएं आदि कार्यान्वित किए गए थे।

9.2 विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रमों से संबंधित अवधारणा और परिभाषाएँ

विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रम अलग-अलग भौतिक और सामाजिक-आर्थिक विशेषताओं के साथ क्षेत्र की विकास चुनौतियों का समाधान करने के लिए डिजाइन किए गए थे। क्षेत्रीय नियोजन की अवधारणा विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रमों पर केन्द्रित है। इसका अर्थ है पिछड़े या कम विकसित क्षेत्र का विकास करना जो इस नियोजन नीति का एक अभिन्न अंग है। शुरुआती चरणों में, भारत में नियोजन ने एक टॉप-डाउन दृष्टिकोण का पालन किया, जिसमें योजना निर्माण के दृष्टिकोण से स्थानीय क्षेत्रों की विशेष आवश्यकताओं का अभाव था। एक अवधारणा के रूप में, क्षेत्रीय योजना को बाद की योजनाओं में पेश किया गया था, खासकर चौथी योजना के बाद। इसलिए, विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रम की पूरी समझ प्राप्त करने के लिए क्षेत्रीय योजना और विकास की बुनियादी अवधारणाओं को समझना आवश्यक है।

9.2.1 क्षेत्र

यह एक भौगोलिक और एक वास्तविक इकाई है जो निश्चित मानदंडों के संदर्भ में प्रकृति में समरूप है। ये पृथ्वी की सतह का हिस्सा हैं, जो आसपास के क्षेत्रों से कुछ परिभाषित तरीकों से प्रतिष्ठित है, जो भूमि, पानी, हवा, जानवरों और पुरुषों और

महिलाओं के परिसर के कारण हो सकते हैं, जिन्हें स्थानिक संबंधों में एक साथ माना जाता है, पृथ्वी की सतह की एक निश्चित स्थिति। एक नियोजन क्षेत्र क्षेत्र का एक खंड है जहां आर्थिक निर्णय लागू होते हैं। यह अवधारणा नियोजन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है क्योंकि यह राष्ट्रीय विकास का एक महत्वपूर्ण उपकरण है।

9.2.2 नियोजन

यह समग्र सामाजिक-आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कुछ विकासात्मक निर्णयों को लागू करने के लिए निर्णय लेने की एक प्रक्रिया है। इसमें उन लोगों के कल्याण के लिए आगे निर्णय लेना शामिल है जो एक साथ एक स्थायी, न्यायसंगत, कुशल और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। नियोजन के दो आयाम हैं अर्थात् निर्माण और कार्यान्वयन।

9.2.3 क्षेत्रीय योजना

क्षेत्रीय नियोजन उप-राष्ट्रीय क्षेत्रों की क्षमता का आकलन करने और उन्हें पूरे राष्ट्र के लिए सर्वोत्तम लाभ के लिए विकसित करने की एक तकनीक है। यह कुशल भूमि उपयोग गतिविधियों और निपटान संरचना विकास से संबंधित है। यह सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से सार्वजनिक कार्रवाई को शामिल करके क्षेत्रीय प्रणाली पर आधारित एक विशिष्ट प्रकार की योजना है। इसका तात्पर्य यह भी है कि क्षेत्रीय नियोजन अंतरिक्ष के संदर्भ में समाज के साथ मौलिक रूप से संबंधित है। क्षेत्रीय नियोजन और विकास की मूल उत्पत्ति क्षेत्रीय असमानता और विशेष रूप से विशेष भौगोलिक क्षेत्रों और पूरे समाज की गहन सामाजिक-आर्थिक विकासात्मक अनिवार्यताओं से उपजी है।

क्षेत्रीय नियोजन क्षेत्रीय आकांक्षाओं, मांगों को पूरा करने, क्षेत्रीय संसाधनों का इष्टतम उपयोग करने, क्षेत्रीय समस्याओं को हल करने, योजना निर्माण और कार्यान्वयन में स्थानीय लोगों को शामिल करने की कोशिश करता है।

9.2.4 कार्यक्रम

यह कुछ दीर्घकालिक लक्ष्यों के साथ संबंधित गतिविधियों का एक सेट है। नियोजन प्रक्रिया में, कार्यक्रमों को एक परिभाषित उद्देश्य के साथ गतिविधियों के एक सेट से जोड़ा जाता है और देश या राज्य की दीर्घकालिक विकासात्मक आवश्यकताओं को प्राप्त करने के लिए लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है। कार्यक्रम उनके इरादे, उद्देश्य और दीर्घकालिक लक्ष्य के संदर्भ में विशिष्ट हैं। कार्यक्रम नियोजन के निर्माण और कार्यान्वयन में समय कारक भी एक महत्वपूर्ण कारक है। प्रत्येक कार्यक्रम संरचना और दृष्टिकोण के संदर्भ में भिन्न होता है। क्षेत्रीय कार्यक्रमों में आम तौर पर, ग्राम पंचायतों, स्थानीय समूहों और पर्यावरण संरक्षण में शामिल स्कूलों जैसे वनीकरण और विशेष रूप से सांस्कृतिक विरासत के रखरखाव के माध्यम से स्थानीय लोग शामिल होते है।

9.2.5 स्पेशल एरिया

ये भौगोलिक स्थिति, सामाजिक संरचना, सांस्कृतिक सेटिंग और आर्थिक समूहों के संदर्भ में अलग-अलग विशेषताओं वाले क्षेत्र हैं। अद्वितीय विशेषताओं के कारण विशेष क्षेत्रों की अपनी विशेष आवश्यकताएं और विकासात्मक आवश्यकताएं हैं। सामान्य योजनाएं और कार्यक्रम विशेष क्षेत्रों की विकास अनिवार्यताओं को पूरा नहीं कर सकते हैं। इसलिए, ऐसे क्षेत्रों के लिए, क्षेत्रीय विकास असमानताओं की चुनौतियों और मुद्दों

ignou THE PEOPLE'S UNIVERSITY

का विकास करने के लिए समय-समय पर विशेष योजनाएं तैयार और कार्यान्वित की जाती हैं। विशेष क्षेत्रों में, मानव विकास के प्रयोजन के लिए संसाधनों के दोहन और उपयोग के माध्यम से सामाजिक-आर्थिक विकास के गतिशील संतुलन को प्राप्त करने के लिए और विशेष कार्यक्रम तैयार करने के लिए क्षेत्र की पारिस्थितिक स्थिति मुख्य मानदंड है।

9.3 विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रमः नीति और कार्यान्वयन

विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रम भारत सरकार की योजना प्रगति का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिसे चौथी पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। यह विभिन्न क्षेत्रों की समस्याओं से निपटने के लिए विशेष आवश्यकता की एक रणनीतिक योजना है क्योंकि उनकी विशिष्ट भू-भौतिक संरचना और स्थान जैसे पहाड़, रेगिस्तान और आदिवासी जैसे सामाजिक रूप से काफी पिछड़े क्षेत्र हैं।

कुछ विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रमों पर संक्षिप्त विचार-विमर्श इस प्रकार हैः

9.3.1 पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एचएडीपी)

पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नामित पहाड़ी क्षेत्रों के लिए शुरू किया गया था। भारत में, कुल 17 प्रतिशत क्षेत्र और 11 प्रतिशत आबादी पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत आती है। नियोजन की दृष्टि से पहाड़ी क्षेत्र को कुल पर्वतीय क्षेत्र के आधार पर दो समूहों में विभाजित किया गया है। पहली श्रेणी उन राज्यों की है जो पूरी तरह से पहाड़ी हैं जैसे जम्मू और कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। इस क्षेत्र को 'विशेष श्रेणी राज्य' कहा जाता है जिसमें बुनियादी ढांचे के विकास, सामाजिक और सामुदायिक सेवाओं पर जोर दिया जाता है।

इसके अलावा, वे पहाड़ी क्षेत्र, जो बड़े राज्यों का हिस्सा हैं, जहां सीमित हिस्से पहाड़ी और अल्पविकास हैं, जिन्हें 'नामित पहाड़ी क्षेत्र' कहा जाता है। मुख्यतः

i) असम के दो जिले - नॉर्थ कछार हिल्स और कार्बी आंगलोंग।

ii) उत्तराखंड के आठ जिले-देहरादून, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, चमोली, उत्तरकाशी, नैनीताल, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़।

iii) पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग जिला।

iv) तमिलनाडु का नीलगिरी जिला।

v) पश्चिमी घाट क्षेत्र के 163 तालुका गोवा, कर्नाटक (40 तालुका), केरल (29 तालुका), महाराष्ट्र (162 तालुका) और तमिलनाडु (29 तालुका) के कुछ हिस्सों को कवर करते हैं।

विकास के स्तर में अंतरराज्यीय असंतुलन को दूर करने के लिए एचएडीपी मुख्य रूप से 1974-75 में इन नामित पहाड़ी क्षेत्रों के लिए पेश किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) की एक समिति ने इसकी सिफारिश की थी। पहाड़ी क्षेत्र की कई विशेषताएं हैं जो इस विशिष्ट विकास योजना के निर्माण के लिए जिम्मेदार हैं, जैसे पहाड़ियों का इलाका, सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक विविधता, जनसंख्या दबाव, वाणिज्यिक और घरेलू उद्देश्यों के लिए वनों की कटाई, मिट्टी के कटाव के कारण भूमि का कम उत्पादक और सड़क विस्तार, स्थानांतरण खेती, अतिचराई, और मोनो संस्कृति वानिकी, आदि।

मुख्य रूप से, एचएडीपी का नियोजन एवं दृष्टिकोण इस कार्यक्रम के तहत कवर किए गए क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग के साथ आर्थिक विकास रहा है। एचएडीपी कार्यक्रम की शुरुआत पहाड़ियों के सामाजिक-आर्थिक विकास और पारिस्थितिक विकास के साथ उनके निवासियों के बुनियादी उद्देश्यों और बुनियादी ढांचे के विकास के माध्यम से बुनियादी जीवन समर्थन प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए की गई थी।

एचएडीपी कार्यक्रमों के अंतर्गत, इन पारिस्थितिक रूप से नाजुक क्षेत्रों को विकसित करने के लिए नामित पहाड़ी क्षेत्रों को विशेष केन्द्रीय सहायता दी जाती है। कार्यक्रम की रणनीति संबंधित राज्य के सभी पहाड़ी क्षेत्रों के लिए एक अलग उप-योजना दृष्टिकोण पर आधारित है। एचएडीपी प्रकोष्ठ की स्थापना योजना तैयार करने और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए की गई थी।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना में लाभार्थी उन्मुख से पारिस्थितिकी-विकास के लिए चार दशकों से अधिक समय से विकसित एचएडीपी का दृष्टिकोण और रणनीति। पारिस्थितिकी सातवीं योजना में पारिस्थितिकी-बहाली, पारिस्थितिकी-संरक्षण और पारिस्थितिकी-विकास पर ध्यान केंद्रित के मुख्य केन्द्र बिन्दु करना था। आठवीं योजना में पहाड़ी अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्र पर विशेष रूप से कृषि पद्धति और घरेलू, कुटीर और ग्रामीण स्तर के लघु उद्योगों के आधुनिकीकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया था। फिर से, जैव-विविधता के सतत उपयोग पर ध्यान केंद्रित करने के साथ पारिस्थितिकी-संरक्षण और पारिस्थितिकी-बहाली की अवधारणा की गई थी। दसवीं योजना का मुख्य उद्देश्य स्थानीय समुदाय की आवश्यकता और आकांक्षाओं तथा जैव विविधता और सतत आजीविका के संरक्षण के लिए रणनीतियों के कार्यन्वयन डिजाइन और कार्यान्वयन में उनकी सक्रिय भागीदारी पर आधारित था। वाटरशेड विकास दृष्टिकोण आगे की योजनाओं में जारी रहा और इसे टिकाऊ तरीके से और पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकियों पर आधारित नाजुक पारिस्थितिकी प्रणालियों को संरक्षित करने के लिए एचएडीपी और डब्ल्यूजीडीपी के माध्यम से लागू किया गया।

पर्वतीय कार्यक्रम के तहत मृदा संरक्षण, बागवानी और वानिकी मुख्य क्षेत्र हैं। भागीदारी दृष्टिकोण में गैर-सरकारी संगठन, आय सृजन की योजनाएं और अंतर-भरने वाली बुनियादी ढांचा योजनाएं शामिल थीं जैसे कि बांस, औषधीय पौधों और कृषि वानिकी की खेती लोगों को सक्षम करने के लिए आजीविका का साधन बनी। एचएडीपी की नियोजन रणनीति की कार्य योजना इस प्रकार है:

i) वन क्षेत्र के साथ-साथ खेती वाले क्षेत्रों के लिए भूमि उपयोग योजना का विकास।

ii) वनस्पति विधियों का उपयोग करके और फसल पैटर्न को बदलकर भूमि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए मिट्टी और पानी का संरक्षण करें।

iii) गरीब लोगों की आय सृजन के लिए उनके उत्थान और पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए गैर-भूमि-आधारित आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना।

iv) वानिकी, वृक्षारोपण, बागवानी, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, पशुपालन, ग्राम और कुटीर उद्योग पारिस्थितिकी विकास के लिए स्वदेशी संसाधनों को प्रोत्साहित करने और उनका पता लगाने के लिए।

v) पारिस्थितिकी बहाली और संरक्षण के लिए बायोस्फीयर जलाशयों, राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभयारण्यों का विकास।

vi) इलेक्ट्रॉनिक्स, फाइबर ऑप्टिक्स, फर्नीचर, कालीन बुनाई और दवाओं और फार्मास्यूटिकल जैसे छोटे पैमाने पर उच्च मूल्य वाले उद्योग पर जोर देना।

vii) पर्यटन उद्योगों को बढ़ावा देना।

viii) अलग-थलग स्थानों और बस्तियों में जनजातियों का आर्थिक उत्थान।

ix) एक व्यापक मानव निपटान नीति विकसित करना और प्रवास को हतोत्साहित करना।

x) ''क्षेत्र-आधारित दृष्टिकोण'' अपनाया गया और सभी वाटरशेड के लिए एकीकृत योजनाएं तैयार की जाएंगी और उपचार के लिए उच्च प्राथमिकता वाले वाटरशेड का चयन किया जाएगा।

xi) वैज्ञानिक हस्तक्षेपों के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा अर्थात रिमोट सेंसिंग आदि का अनुप्रयोग।

xii) गैर-अभिसमय ऊर्जा स्रोतों अर्थात सौर, पनबिजली, जैव गैस आदि को बढ़ावा देना ।

xiii) झूम की खेती को रोकें और इस तरह के वृक्षारोपण कृषि में झूमिया का पुनर्वास करें, जिससे वे उत्तरोत्तर वृक्षारोपण संपत्ति के मालिक बन जाएं।

xiv) स्थानीय स्तर पर सामाजिक संसाधनों के प्रबंधन में गैर-सरकारी संगठनों, स्थानीय लोगों को शामिल करते हुए सभी विकास में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना।

नौवीं पंचवर्षीय योजना में एचएडीपी के लिए उपलब्ध विशेष केन्द्रीय सहायता (एससीए) को अब एचएडीपी के अंतर्गत नामित पहाड़ी क्षेत्रों और पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम के नामित तालुकों के बीच 60:40 के अनुपात में विभाजित किया गया है। एससीए को क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों के आधार पर विभाजित किया गया है जो समान महत्व देते हैं। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में नीलगिरि जिले में एचएडीपी के तहत कार्यान्वयन के लिए कुल 211.48 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। मृदा संरक्षण (22.51 प्रतिशत), अनुसूचित जाति (26.3 प्रतिशत), अनुसूचित जनजाति (11.02 प्रतिशत), वानिकी (18.44 प्रतिशत), बागवानी के कल्याण जैसे प्रमुख क्षेत्रों के लिए निधियां निधियों का मुख्य हिस्सा (11.39:,) स्थानीय निकायों (ग्रामीण 18.64 प्रतिशत और शहरी निकायों 24.94 प्रतिशत) और सड़क क्षेत्र (13.63 प्रतिशत) के विकास के लिए आवंटन किया गया। बारहवीं योजना के लिए 6336 करोड़ रुपए प्रति वर्ष की दर से व्यय करने के लिए परिव्यय निधि 31680 करोड़ रुपए थी।

एचएडीपी के कार्यान्वयन की रणनीति समय के साथ बदल गई है। जोर व्यक्तिगत उन्मुख योजनाओं से क्षेत्र-आधारित दृष्टिकोण की ओर स्थानांतरित हो गया है। नीलगिरी ने वाटरशेड आधारित योजनाओं को अपनाया है क्योंकि मृदा और जल संरक्षण उपायों जैसे क्षेत्र आधारित कार्यक्रम को अधिक प्रभावी ढंग से शुरू किया जा सकता है। इस स्कीम के अंतर्गत वाटरशेडों की संसाधन सूचना एकत्र की गई और सुदूर संवेदन तकनीकों के माध्यम से उनका विश्लेषण किया गया जिसके आधार पर इसरो, बेंगलुरू ने नीलगिरि जिले की वाटरशेड सीमाओं और कृषि इंजीनियरिंग, बागवानी और वन विभागों के समन्वय से सत्यापित सीमाओं को चित्रित किया है। नीलगिरि जिला भवानी, मोयार और कबिनी जैसी प्रमुख नदियों द्वारा बहाया जाता है,

जो कावेरी और पांडियन की सहायक नदियाँ हैं। ड्रेनेज पैटर्न के आधार पर पूरे जिले को 75 प्रमुख वाटरशेड में चित्रित किया गया है। मृदा संरक्षण, बागवानी और वानिकी इस कार्यक्रम के तहत मुख्य क्षेत्र हैं। इसके अलावा, पर्याप्त धनराशि प्रदान करके अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कल्याण, मानव संसाधन विकास, स्थानीय निकायों के विकास, सड़कों, पर्यटन, इंडको चाय कारखानों, खादी और ग्रामोद्योग और रेशम उत्पादन आदि को भी महत्व दिया जाता है।

वार्षिक फसल कवरेज और पहलुओं के क्रम में पूरे वाटरशेड को उच्च प्राथमिकता वाले वाटरशेड के रूप में पहचाने जाने वाले दस-वाटरशेड के साथ प्राथमिकता दी जाती है। विभिन्न क्षेत्रीय शीर्षों के अंतर्गत योजनाओं के बेहतर समन्वय और कार्यान्वयन के लिए रेखांकित वाटरशेड को सूक्ष्म वाटरशेड में विभाजित किया गया है, जिनमें से प्रत्येक में 300-500 हेक्टेयर का क्षेत्र शामिल है। वर्ष 1995-96 से वाटरशेड दृष्टिकोण अपनाकर एनजीओ के साथ स्थानीय लोगों को शामिल करने के अलावा पारिस्थितिकी को स्थिर करने के लिए कोर सेक्टरों की गतिविधियों को अन्य लाइन विभाग के साथ एकीकृत किया गया है। एकीकृत वाटरशेड आधार पर प्राथमिकता वाले वाटरशेड की पहचान करना और वाटरशेड कार्यों के अलावा अन्य के लिए 40% जिसमें एचएडीपी के तहत बनाई गई परिसंपत्तियों के रखरखाव के लिए 15% और स्थापना लागत के लिए 10% शामिल हैं।

किसानों और स्थानीय लोगों को अपनी जरूरतों के लिए योजना बनाने में शामिल करने के लिए, एनजीओ सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन बैठकें करता है जिसमें वाटरशेड समुदाय अपने विचार व्यक्त करने और सुधारात्मक उपायों का सुझाव देने के लिए भाग लेते हैं।

9.3.2 जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (टीएडीपी)

आदिवासी आबादी की संख्या और उनकी स्थिति देश में एक विविध तस्वीर प्रस्तुत करती है। कुछ क्षेत्रों में मिजोरम, लक्षद्वीप और मेघालय जैसे उच्च जनजातीय घनता है, जबकि अन्य क्षेत्रों में, आदिवासी कुल आबादी का केवल एक छोटा सा हिस्सा बनाते हैं। आदिवासी क्षेत्र मुख्य रूप से भौगोलिक रूप से पहाड़ी, वनाच्छादित और शुष्क प्रकृति के हैं, इसके कारण सामाजिक-आर्थिक विकास बहुत धीमा हुआ है।

कुछ आदिवासी समूह हैं, जो अभी भी भोजन इकट्ठा करने के चरण में हैं, और खेती को स्थानांतरित करने या कृषि के आदिम रूपों का पीछा करने का अभ्यास करते हैं। समाज के अन्य समूहों द्वारा जनजातियों के शोषण को रोकने और उन्हें मुख्यधारा में लाने के लिए, हमारा संविधान उनके सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए भी प्रावधान करता है ।

1976 तक, आदिवासी क्षेत्र देश के विकास से बहुत दूर थे और विभिन्न समस्याओं का सामना कर रहे थे। विस्तृत और व्यापक समीक्षा के बाद, पांचवीं पंचवर्षीय योजना में विशिष्ट प्रयास किए गए क्योंकि उनकी आवश्यकताएं और समस्याएं उनकी भौगोलिक जनसांख्यिकीय एकाग्रता के आधार पर भिन्न होती हैं। जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम को 50 प्रतिशत या उससे अधिक जनजातीय एकाग्रता वाले क्षेत्रों के लिए एक एकीकृत कार्यक्रम के रूप में नोट किया गया था। जनजातियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने और देश के अन्य हिस्सों से विकास के स्तर के बीच अंतर को कम करने के उद्देश्य से ऐसे क्षेत्रों के लिए उप-योजना तैयार करने को महत्व दिया जाता है।

आदिवासी क्षेत्र उप-योजना दृष्टिकोणः आदिवासी समुदायों की समस्या से निपटने के लिए, आदिवासी उप-योजना के रूप में, आदिवासी विकास के लिए लागू किया गया था। जनजातीय विकास के लिए यह लागू की गई है। उप-योजना दृष्टिकोण 19 राज्यों 2 केंद्र शासित प्रदेशों में यह लागू की गई है। इसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेशों, झारखंड और राजस्थान के व्यापक क्षेत्र शामिल हैं। जनजातीय क्षेत्रों को सूक्ष्म (ब्लॉक-स्तर), माईक्रो (उप-मंडल/तहसील), और मैक्रो (राज्य-स्तर) के रूप में तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है। अन्य में वार्ड विकास खंड को नई रणनीतिक योजना में विकास की सबसे छोटी इकाई के रूप में लिया गया। इसे एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना (आईटीडीपी) के रूप में जाना जाता है। जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के महत्वपूर्ण पहलू निम्नानुसार हैंः

i) परिवार उन्मुख कार्यक्रम के रूप में बागवानी, पशुपालन और लघु उद्योग आदि में लाभार्थी परिवार के उत्पादकता स्तर को बढ़ाने के लिए।

ii) भूमि हथियाने वाले साहूकारों, ऋण-पट्टी, वन-श्रम आदि के शोषण से मुक्त करना।

iii) शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना।

iv) जनजातीय क्षेत्रों में ढांचागत सुविधाएं उपलब्ध कराना।

जनजातीय विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत कुल 180 आईटीडीपी इकाइयां चलन में हैं। जनजातीय क्षेत्र कार्यक्रम के स्थानिक वितरण से यह स्पष्ट है कि मध्य भारत ज्यादातर जनजातीय उप-योजना के अंतर्गत आता है। उप-योजना के लिए धन राज्य योजना, केंद्रीय मंत्रालयों से केंद्रीय परिव्यय, विशेष केंद्रीय सहायता और संस्थागत वित्त से आता है। जनजातीय कार्यक्रम के लिए दी जाने वाली केंद्रीय सहायता राशि को क्षेत्रवार विभाजित किया जा सकता है। यानी शिक्षा, आर्थिक उत्थान और स्वास्थ्य। इस कार्यक्रम के तहत जनजातीय आबादी को प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाएं मुफ्त शिक्षा, शैक्षिक उपकरणों का प्रावधान, स्कूल, छात्रवृत्ति आदि हैं। इस योजना के चलते कई भारत के समुदाय अपनी आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति में सुधार कर रहे हैं।

ऐसी परियोजनाओं की सबसे बड़ी संख्या मध्य भारत में रही है। मध्य प्रदेश में 49, उड़ीसा में 21, असम में 19, महाराष्ट्र में 16, बिहार में 14 और पश्चिम बंगाल में 12 मामले हैं। कुल मिलाकर, कुल परियोजनाओं में से दो-तिहाई से अधिक इन राज्यों में हैं। सातवीं योजना के दौरान आईटीडीपी के अंतर्गत कुल एरियल कवरेज में देश का 15.27 प्रतिशत क्षेत्र शामिल था। मणिपुर (90.03 प्रतिशत), सिक्किम (63.49 प्रतिशत) और त्रिपुरा (63.8 प्रतिशत) राज्यों के प्रमुख हिस्से ऐसी परियोजनाओं के अंतर्गत थे। बड़े क्षेत्रों वाले अन्य राज्यों में ओरिसा (44.2 प्रतिशत), हिमाचल प्रदेश (43.03 प्रतिशत), मध्य प्रदेश (36.9 प्रतिशत) और बिहार (25.1 प्रतिशत) शामिल हैं।

राज्य और केंद्र सरकार के कई प्रयासों के बावजूद कुछ आधारभूत समस्याओं के कारण आदिवासी बहुत लाभान्वित नहीं हुए हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि गैर-आदिवासी अब पर्याप्त संख्या में आदिवासी बहुल क्षेत्रों में पलायन कर रहे हैं। दूसरी ओर आदिवासी शैक्षिक और रोजगार के अवसरों की तलाश में अन्य क्षेत्रों में पलायन कर रहे हैं। किसी भी प्रशासनिक इकाई में आदिवासी आबादी लंबे समय तक बहुमत में नहीं रह सकती है। इसलिए इस नई चुनौती से निपटने के लिए सक्रिय होना जरूरी है।

जनजातीय क्षेत्र कार्यक्रम की कमजोरियों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है और इसे सुदृढ़ करके देश की मुख्यधारा में उनका अस्तित्व और भागीदारी संभव हो सकती है ।

9.3.3 पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम (डब्ल्यूजीडीपी)

उत्तर में हिमालयी क्षेत्र के पर्वतीय क्षेत्र या पहाड़ी क्षेत्र और दक्षिण में पश्चिमी घाट क्षेत्र कई प्रमुख नदी प्रणालियों के स्रोत, जलग्रहण और वाटरशेड प्रवाहित करते हैं, वे जंगलों, पौधों, जानवरों और खनिज संपदा में समृद्ध होते हैं। उनके पास बहुत उपजाऊ और बहुत संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र हैं। पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के साथ पहाड़ों की एक श्रृंखला है जो लगभग 1600 किमी लंबी और 80 से 100 किमी चौड़ी है जो केरल के पालघाट जिले में निरंतरता में रुकावट के साथ महाराष्ट्र से तमिलनाडु तक लगातार चलती है। पश्चिमी घाट देश के पर्वतीय क्षेत्र का 8.82 प्रतिशत हिस्सा है। पश्चिमी घाट के पहाड़ी पारिस्थितिकी तंत्र सबसे अमीर वनस्पतियों और जीवों में से एक हैं और 30 प्रतिशत क्षेत्र जंगल के तहत हैं। पश्चिमी घाट रेंज प्रायद्वीपीय भारत की जलवायु, अर्थव्यवस्था और सामाजिक परिवेश को आकार देने में एक महत्वपूर्ण निर्धारक है। पश्चिमी घाट क्षेत्र तमिलनाडु का एक हिस्सा है जो आठ जिलों के 33 तालुकों में फैला हुआ हैः कोयंबटूर, तिरुपुर, डिंडीगुल, थेनी, मदुरै, विरुधुनगर, तिरुनेलवेली और कन्याकुमारी। यह तमिलनाडु का 20 प्रतिशत है। पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम (डब्ल्यूजीडीपी) 1975-76 में शुरू हुआ। यह कार्यक्रम आर्थिक विकास कार्यक्रमों के साथ चिंताओं के साथ शुरू हुआ लेकिन सामाजिक-आर्थिक, बुनियादी ढांचे और पारिस्थितिक विकास की ओर ध्यान केंद्रित किया गया।

डब्ल्यूजीडीपी को 100 प्रतिशत केंद्रीय सहायता के साथ शुरू किया गया था और अब इसे केंद्र और राज्य सरकार के बीच 90:10 के अनुपात में साझा किया जाता है। इसके तहत कार्यक्रम 70 प्रतिशत संसाधन उन योजनाओं के लिए आरक्षित हैं जो मिट्टी और जल संरक्षण, वानिकी और बुनियादी ढांचे के विकास जैसी स्थायी आजीविका को बढ़ावा देते हैं। वाटरशेड को उत्पादन में वृद्धि और स्थिरीकरण, पारिस्थितिक क्षरण को कम करने, क्षेत्रीय असमानता में कमी और ग्रामीण गरीबों के लिए अधिक से अधिक आजीविका के अवसरों को खोलने के लिए एक बुनियादी उपचार इकाई के रूप में अपनाया जाता है। वर्ष 2010-11 से डब्ल्यूजीडीपी कार्यान्वयन स्कीमों के लिए वाटरशेड दृष्टिकोण पर बल दिया गया था। यह स्थानीय भागीदारी के साथ एक एकीकृत दृष्टिकोण है। ग्यारहवीं योजना के दौरान 101.16 करोड़ रुपये की लागत से 166 वाटरशेडों में मृदा और जल संरक्षण के उपाय किए गए, जिसमें मृदा संरक्षण क्षेत्र पर 36.63 करोड़ रुपये और वानिकी क्षेत्र पर 19.10 करोड़ रुपये खर्च किए गए।

विकास का दायरा : पश्चिमी घाट क्षेत्र वन, बागवानी, पशुपालन के विकास और भूजल को रिचार्ज करने के साथ-साथ पीने के प्रयोजनों के लिए पानी की उपलब्धता में सुधार के लिए गुंजाइश प्रदान करता है। पश्चिमी घाट के विकास से पारिस्थितिक उन्नयन और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में भी मदद मिलेगी। इसमें चाय, कॉफी, इलायची, कोको, रबर, काली मिर्च आदि बागान फसलों के तहत क्षेत्र बढ़ाने की भी गुंजाइश है।

योजना (डब्ल्यूजीडीपी) अवधियों में पश्चिमी घाट क्षेत्र का विकासः पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, डब्ल्यूजीडीपी पहाड़ी क्षेत्रों में स्थानीय आबादी की आर्थिक

भलाई और पहाड़ी क्षेत्र के संसाधनों के दोहन पर जोर देता है। क्षेत्र में मुख्य गतिविधियों में बागवानी, वृक्षारोपण, वनीकरण, लघु सिंचाई, पशुपालन और पर्यटन शामिल हैं। छठी पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से प्रायोगिक आधार पर अवसंरचनात्मक विकास स्कीमों पर केन्द्रित है। सातवीं और आठवीं पंचवर्षीय योजना मानव गतिविधियों के कारण होने वाले पारिस्थितिक नुकसान को बहाल करने के लिए आनुवंशिक विविधता को संरक्षित करने के लिए एक जीवन समर्थन प्रणाली पर आधारित थी। नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान डब्ल्यूजीडीपी के तहत विकास योजनाओं के उद्देश्य पर्यावरण के अनुरूप विकास और नाजुक प्रणालियों को परेशान किए बिना विकास थे। दसवीं पंचवर्षीय योजना में स्थानीय समुदायों की जरूरतों और आकांक्षाओं को पहचानते हुए जैव विविधता के सतत उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया गया था। इस कार्यक्रम के तहत, शुरू की गई मुख्य गतिविधियां मृदा संरक्षण, बागवानी, वानिकी, लघु सिंचाई, ग्रामीण सड़कें, पशुपालन, मत्स्य पालन, रिमोट सेंसिंग और ताड़ उत्पादों का विकास हैं। डब्ल्यूजीडीपी के मुख्य उद्‌देश्य निम्ननुसार हैः

i) वन संरक्षण और संरक्षण के माध्यम से पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखें जो जीवन समर्थन प्रणाली के लिए आवश्यक है।

ii) मानव गतिविधियों के कारण पारिस्थितिक क्षति को बहाल करने के लिए आनुवंशिक विविधता को संरक्षित करना।

iii) लोगों के बीच जागरूकता पैदा करना और उन्हें पारिस्थितिक क्षरण के गंभीर परिणामों के बारे में शिक्षित करना, इसलिए वे पारिस्थितिकी-विकास में सक्रिय भागीदारी निभाते हैं।

iv) मृदा और जल संरक्षण के लिए नदियों, झीलों, दलदलों, जलाशयों और झरनों के आसपास के क्षेत्र के मिट्टी के कटाव और विनाश की जांच करना।

v) वृक्षावरण बढ़ाने के लिए वनीकरण और वानिकी कार्यक्रम।

vi) ग्रामीण जनजातीय आबादी के लिए ईंधन, चारा, लकड़ी और औषधीय सामग्री जैसे वन उत्पादों जैसी बुनियादी आजीविका आवश्यकताओं को पूरा करना।

vii) महिलाओं की सहभागिता से बड़े पैमाने पर जन आंदोलन खड़ा करना।

9.3.4 सूखा प्रवण क्षेत्र विकास कार्यक्रम (डीपीएडीपी)

भारत में भूमि उपयोग का एक बड़ा हिस्सा सूखा प्रवण है और शुष्क और अर्ध-शुष्क श्रेणियों में आता है। शुष्क, अर्ध-शुष्क या उप-आर्द्र देश में सूखा प्रवण क्षेत्रों का सीमांकन करने के लिए विभिन्न श्रेणियां हैं। सूखा शुष्क मौसम की एक दीर्घकालिक अवधि है जो एक निश्चित अवधि के लिए सामान्य वर्षा में कमी के कारण होती है। सूखा भूमि के क्षरण, घटते जल संसाधनों, फसलों, मानव संसाधनों और पशुधन की उत्पादकता में कमी की स्थिति है। यह संकट के दौरान भूख, कुपोषण, मानव और मवेशी आबादी दोनों के आउट-माइग्रेशन की विशेषता है। भारत में, भूमि द्रव्यमान का एक बड़ा हिस्सा बहुत कम वर्षा और अत्यधिक जलवायु परिस्थितियों के कारण इन स्थितियों के अंतर्गत आता है। डीपीएपी इस प्रकार के क्षेत्र के लिए एक विशेष क्षेत्र कार्यक्रम है जिसे विशेष रूप से सूखे जैसी स्थितियों से प्रभावित स्थानों की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है।

ड्राफ्ट प्रवण क्षेत्र देश में क्षेत्रीय असंतुलन पैदा करने के लिए महत्वपूर्ण कारक थे। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी) पहली बार 1970-71 में सूखा क्षेत्रों की समस्या से निपटने के लिए ग्रामीण कार्यक्रम (आरडब्ल्यूपी) के रूप में शुरू किया गया था। 1973-74 में चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान इसे क्षेत्र विकास कार्यक्रम में बदल दिया गया था। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भूमि, जल और पशुधन संसाधनों का इष्टतम उपयोग, मुद्रा का विकास, मिट्टी और नमी संरक्षण, सामाजिक और कृषि वानिकी, पशुधन विकास और डेयरी विकास पर अधिक जोर देने के साथ वनीकरण, फसल पैटर्न का पुनर्गठन, आर्थिक स्थिति में वृद्धि करके सुधार करना है समाज के गरीब और वंचित वर्गों की आय बढाना भी इसका उद्देश्य है।

सूखा प्रवण क्षेत्रों में मानव और पशुधन आबादी के तीव्र दबाव ने मिट्टी के कटाव, गिरते जल स्तर और वनस्पति आवरण को कम करने के मुद्दों पर जोर देते हुए प्राकृतिक संसाधनों को कम कर दिया है। योजना समिति आयोग की सिफारिश के बाद, डीपीएपी ने इसके लिए एक एकीकृत क्षेत्र विकास दृष्टिकोण का पालन किया।

प्रारंभ में, यह कार्यक्रम केंद्र और राज्य के 50-50 साझाकरण के साथ शुरू किया गया था। कार्यान्वयन की दृष्टि से, कठोर दिशानिर्देशों और एक गलत डिजाइन किए गए ढांचे के कारण कार्यक्रम शुरुआत में बहुत सफल नहीं था। लोगों की भागीदारी और बुनियादी सुविधाओं अभाव इस कार्यक्रम की मुख्य खामिया थी। 1995-96 से वाटरशेड कार्यक्रम पेश किया जा रहा है, बाद में और इस कार्यक्रम की कार्यान्वयन इकाई को वाटरशेड परियोजना में बदल दिया गया था। स्थानीय लोग वाटरशेड परियोजनाओं की योजना और विकास में सक्रिय रूप से शामिल हैं। फंड शेयरिंग रेशियो को भी संशोधित कर 75:25 कर दिया गया। कुछ अनुमानों के अनुसार, डीपीएपी का प्रचालन 16 राज्यों आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्णाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में किया जा रहा है, 195 जिलों और 972 ब्लॉकों में 746 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र की कवरेज है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कुल परिव्यय योजना 10,000 करोड़ रुपए थी। जिसमें 1000 करोड़ रु. 500 करोड़ रुपये केंद्र का हिस्सा था।

डीपीएपी के कार्यान्वयन के लिए प्रत्येक राज्य का अपना संगठनात्मक ढांचा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से सिंचाई परियोजनाओं, भूमि विकास कार्यक्रमों, वनीकरण, घास के मैदान के विकास, ग्रामीण विद्युतीकरण और बुनियादी ढांचे के विकास के अन्य कार्यक्रमों जैसे सड़कों, बाजार, सर्विसिंग, प्रसंस्करण और क्रेडिट, आदि पर मुख्य जोर दिया जा रहा है।

समाज के अन्य कमजोर वर्गों और महिलाओं को भी पर्याप्त योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया गया। सामुदायिक भागीदारी और वाटरशेड दृष्टिकोण की भूमिका को कार्यक्रम कार्यान्वयन में केंद्रीय विषय बनाया गया था। इसके अलावा, सभी विकास कार्यक्रमों के एक एकीकृत दृष्टिकोण और अभिसरण और प्रभावी निगरानी और कार्यान्वयन ने डीपीएपी को पुनर्जीवित किया।

भूमि विकास, जल संसाधन विकास और वनीकरण और चरागाह विकास को प्रोत्साहित किया गया। इस कार्यक्रम के तहत वैकल्पिक व्यवसायों और आर्थिक विविधीकरण के अवसर भी विकसित किए जाते हैं।

9.3.5 मरुस्थल विकास कार्यक्रम (डीडीपी)

मरुस्थल विकास कार्यक्रम (डीडीपी) राष्ट्रीय कृषि आयोग (1974) की सिफारिशों पर 1977-78 में शुरू किया गया था। रेगिस्तान बेहद शुष्क क्षेत्र हैं जहां एक वर्ष में 25 सेमी. से कम वर्षा होती है। एक रेगिस्तानी क्षेत्र में कोई या बहुत कम वनस्पति होती है, बेहद कम वर्षा, कम आर्द्रता और अत्यधिक तापमान भारत में पाए जाने वाले दोनों प्रकार के रेगिस्तान यानी ठंडे रेगिस्तान और गर्म रेगिस्तान को कवर करता है। ठंडे रेगिस्तान केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिलों में पाए जा सकते हैं जबकि गर्म रेगिस्तान राजस्थान, गुजरात और हरियाणा के पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं। डीडीपी ऐसे स्थानों के लिए एक विशेष क्षेत्र कार्यक्रम है।

डीडीपी का प्रमुख उद्देश्य मरुस्थलीकरण की प्रक्रियाओं को नियंत्रित करना, सिंचाई, वनीकरण, मृदा और जल संरक्षण, शुष्क भूमि कृषि, भूजल विकास, पशुधन विकास और मानव संसाधन विकास जैसी विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से उत्पादन के स्तर को बढ़ाने के अवसरों को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य, लोगों और आजीविका पर विचार करके वाटरशेड आधार पर ऐसी अवक्रमित भूमि का विकास करना। इसका उद्देश्य सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और इसके प्रतिकूल प्रभाव को कम करना भी है।

सूखा प्रभावित क्षेत्र, आजीविका के नुकसान को कम करते हैं, पशुधन प्रबंधन, और स्थानीय सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करके पारिस्थितिक संतुलन बहाल करते हैं।

प्रारंभ में, इसे एक अलग तरीके से लागू किया गया था, लेकिन बाद में वाटरशेड दृष्टिकोण अपनाया गया था। 1995 से वाटरशेड विकास कार्यक्रम का एक हिस्सा है। अब सात राज्यों के विभिन्न चरणों में 1747 वाटरशेड परियोजनाएं हैं। प्रारंभ में, केंद्र और राज्य द्वारा 75:25 के आधार पर धन आवंटित किया गया था, लेकिन वर्तमान में यह 100 प्रतिशत केंद्रीय सहायता है। आबंटन का कम से कम 75% उन गतिविधियों के लिए निर्धारित किया गया है जो मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया का मुकाबला करने में योगदान देंगे। डीडीपी को क्षेत्रीय आधार पर कार्यान्वित किया गया था और आनुपातिक भार जिसमें वनीकरण और मुद्रा विकास (40%), जल संसाधन विकास (20%), आदि को अधिकतम दिया गया था, निधि आवंटन 24 लाख रुपये प्रति 1000 वर्ग किमी की दर से है। प्रति जिला 5000 लाख रुपये की सीमा के साथ शुरू किया गया। हिमाचल प्रदेश के लिए 100 लाख रुपये का एकमुश्त प्रावधान किया गया है। जम्मू-कश्मीर के लिए 150 लाख रुपये रखे गए।

कमजोर वर्गों, स्वैच्छिक संगठनों की भागीदारी, परिसंपत्तियों के निर्माण और प्रभावी निगरानी और मूल्यांकन के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण का उपयोग करने का भी सुझाव दिया गया था। डीडीपी 7 राज्यों के 235 ब्लॉकों, 40 जिलों में 45.8 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करके कार्यान्वित किया जा रहा है। इसमें आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, राजस्थान (सभी गर्म-रेगिस्तानी क्षेत्र), और हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर (ठंडे-रेगिस्तानी क्षेत्र) शामिल हैं। वाटरशेड दृष्टिकोण डीडीपी कार्यान्वयन की कुंजी है। संसाधन सूची इसे लागू करने से पहले सबसे महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि यह क्षेत्र-विशिष्ट समस्याओं को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। वर्ष 1995-96 से इसका अनुसरण किया जा रहा है लेकिन अभी भी लंबा रास्ता तय करना है क्योंकि डीडीपी के अंतर्गत केवल 5 प्रतिशत क्षेत्र लक्षित है और यह पूरा देश है? यह अंत में, यह कार्यक्रम मरुस्थलीकरण प्रक्रिया को नियंत्रित करने, प्रभावित सूखा

प्रवण क्षेत्रों को कम करने, प्रभावित क्षेत्रों में पारिस्थितिक संतुलन बहाल करने और भूमि जल पशुधन और मानव संसाधनों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था। कुल आवंटित निधियों में से, मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया का मुकाबला करने के लिए कम से कम 75% का योगदान दिया गया है।

9.3.6 सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी)

सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम सातवीं पंचवर्षीय योजना के तहत देश के पश्चिमी क्षेत्र में संवेदनशील सीमा के संतुलित विकास के उद्देश्य से शुरू किया गया था। कुल परिव्यय 200 करोड़ रुपये था। इस कार्यक्रम में बुनियादी सुविधाओं और स्थानीय लोगों के बीच सुरक्षा की भावना को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। इस कार्यक्रम को शुरू करने में पंजाब, राजस्थान और गुजरात राज्यों को शामिल किया गया था, लेकिन बाद में जम्मू और कश्मीर तक विस्तारित किया गया। गृह मंत्रालय के तहत 1986-87 में योजनाएं शुरू की गई थीं। कार्यक्रम का मुख्य जोर सीमा से सटे सामुदायिक विकास खंडों में मानव संसाधन, विशेष रूप से स्कूली शिक्षा-तकनीकी और व्यावसायिक के विकास पर केंद्रित था। कार्यक्रम में चार तत्व शामिल हैं अर्थात फोटो पहचान पत्र जारी करना लक्षित क्षेत्रों की आबादी, शिक्षा, सिंचाई और इन क्षेत्रों के सामाजिक-आर्थिक विकास पर अनुसंधान अध्ययन करना आदि।

वर्ष 1990-91 और 1991-92 में, दोनों वर्षों में वार्षिक परिव्यय लगभग 85 करोड़ रुपये था। आठवीं योजना के दौरान कवरेज को पूर्वी क्षेत्र तक बढ़ाया गया, उस दायरे की भी समीक्षा की गई, जिसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा की समस्या का ध्यान रखा जा सकता है, न कि सामान्य विकास योजनाओं के लिए। आठवें प्लान इस कार्यक्रम के लिए 640 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। बाद में, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और अन्य संबद्ध क्षेत्रों जैसे अन्य सामाजिक-आर्थिक पहलुओं को शामिल करने के लिए कार्यक्रम के दायरे का विस्तार किया गया। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, कवरेज को पूर्वी राज्यों को शामिल करने के लिए बढ़ाया गया था जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते थे। बीएडीपी योजना का कार्यान्वयन पंचायती राज संस्थानों, स्वायत्त परिषदों और स्थानीय निकायों के माध्यम से सहभागी और विकेंद्रीकृत आधार पर किया गया था। बीएडीपी के दिशा-निर्देशों को फरवरी, 2009 में संशोधित किया गया था और संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार बीएडीपी में 362 सीमा ब्लॉक शामिल हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं और 17 राज्यों के 96 सीमावर्ती जिलों के अंतर्गत आते हैं।

9.4 आइए संक्षेप में बताते हैं

समावेशी और संतुलित क्षेत्रीय विकास भारत की नियोजन नीति का मूल सिद्धांत रहा है। भारत का आकार और विविधता ऐसी है कि संतुलित क्षेत्रीय विकास के लिए आदर्श योजना अभी भी एक दूर का सपना है। समय के साथ, क्षेत्रों के बीच असमानता कम होने के बजाय बढ़ी है। देश के कुछ क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिए स्थलाकृतिक बाधाओं और प्राकृतिक बाधाओं पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। देश में विकास संसाधनों के असमान वितरण और प्रतिकूल भू-भौतिक संरचना के संदर्भ में भिन्नता का कारण बना है। विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रमों को एससीए के रूप में धन के अधिक खुले हस्तांतरण के माध्यम से इन क्षेत्र-विशिष्ट पिछड़ेपन को दूर करने और रणनीतिक योजनाएं निर्धारित करने का निर्देश दिया जाता है। पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम, जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, सूखा प्रवण

ignou THE PEOPLE'S UNIVERSITY

क्षेत्र कार्यक्रम, पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम जैसे कई कार्यक्रम समग्र रूप से अनुरूप हैं विशिष्ट क्षेत्र का विकास। निगरानी और मूल्यांकन के लिए विभिन्न एजेंसियों की भागीदारी इन कार्यक्रमों को सफल बनाती है।

9.5 मुख्य शब्द

क्षेत्रः यह एक भौगोलिक और वास्तविक इकाई है जो निश्चित मानदंडों के संदर्भ में प्रकृति में समरूप है। पृथ्वी की सतह के एक हिस्से के रूप में क्षेत्र, आसपास के क्षेत्रों से कुछ परिभाषित तरीकों से प्रतिष्ठित है।

विशेष क्षेत्रः यह भौतिक सेटिंग, भौगोलिक स्थिति, सामाजिक संरचना, सांस्कृतिक सेटिंग और आर्थिक समूहों के संदर्भ में विशेष विशेषताओं वाला क्षेत्र है। विशेष क्षेत्र जिनकी कुछ विशेष आवश्यकताएं हैं और जिनकी आवश्यकता है क्षेत्रीय विकास असमानताओं की चुनौतियों और समस्याओं का समाधान करने के लिए ध्यान दें।

क्षेत्रीय योजनाः यह सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से सार्वजनिक कार्रवाई को शामिल करके क्षेत्रीय प्रणाली पर आधारित एक विशिष्ट प्रकार की योजना है। इसका तात्पर्य यह भी है कि क्षेत्रीय नियोजन अन्तराल (भिन्नता) के संदर्भ में समाज के साथ मौलिक रूप से संबंधित है। क्षेत्रीय नियोजन और विकास की मूल उत्पत्ति क्षेत्रीय असमानता और विशेष रूप से विशेष भौगोलिक क्षेत्रों और समग्र रूप से समाज की गहन सामाजिक-आर्थिक विकास अनिवार्यताओं से उपजी है।

रेगिस्तानः रेगिस्तान एक वर्ष में 25 सेमी. से कम वर्षा के साथ अति शुष्क क्षेत्र है। एक रेगिस्तान में कोई या बहुत कम वनस्पति, बेहद कम वर्षा, कम आर्द्रता और अत्यधिक तापमान की विशेषता है। तापमान के आधार पर रेगिस्तान दो प्रकार का होता है यानी ठंडा रेगिस्तान और गर्म रेगिस्तान।

जनजातीय उप-योजना दृष्टिकोणः दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए गतिविधियों के सेट के साथ जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए उपयोग किया जाने वाला एक नियोजन दृष्टिकोण। नियोजन प्रक्रिया में, देश या राज्य की दीर्घकालिक विकासात्मक आवश्यकताओं को प्राप्त करना महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम अपने इरादे, उद्देश्य और दीर्घकालिक लक्ष्य के संदर्भ में विशिष्ट हैं। कार्यक्रम नियोजन के निर्माण और कार्यान्वयन में समय कारक भी एक महत्वपूर्ण कारक है। प्रत्येक कार्यक्रम संरचना और दृष्टिकोण के संदर्भ में भिन्न होता है।

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

9.6 सुझाए गए अध्ययन और संदर्भ

मिश्रा, आर.पी., (1992)। क्षेत्रीय योजनाः अवधारणा, तकनीक और नीतियां, अवधारणा, नई दिल्ली।

सिंह, आर.पी., (2011)। ग्रामीण विकासः सिद्धांत और व्यवहार, सरोज प्रकाशन।

सिंह, रणवीर, ''भारत में जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रमय इंट में मुद्दा और चुनौतियां'' जर्नल ऑफ सोशल साइंस, वॉल्यूम 8, अंक 4 अप्रैल 2018, आईएसएसएन नं। 2249-2496।

वेबसाइटः https://niti.gov.in/planningcommission.gov.in https://tsp.apcfss.in/files/127-pdf

P.त्रिनाधा राव, एम। गोपीनाथ रेड्डी, जोस चथुकुलम (2012): जनजातीय उप-योजना (टीएसपी) रणनीति का कार्यान्वयनः आजीविका और प्राकृतिक संसाधनों के लिए आंध्र प्रदेश अनुसंधान इकाई में आदिवासियों की आजीविका पर प्रभाव,